tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

चेन्नई सुपर किंग्स को झटका, आयुष म्हात्रे पूरे सीजन से बाहर
Page-04

राहिल देशमुख की धमाकेदार एंट्री, 'राजा शिवाजी' में दिखा जलवा
Page-05

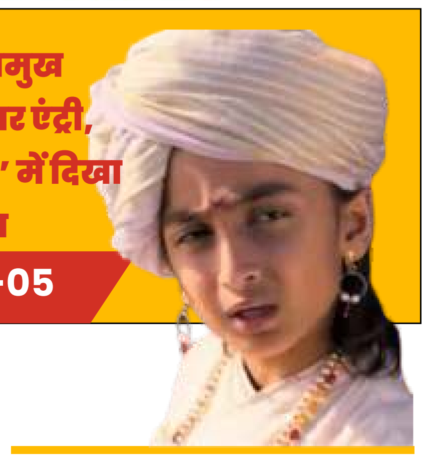

(यूएई) ने 1 मई से OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा की

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 1 मई से तेल उत्पादक देशों के प्रमुख समूहों OPEC और OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने पहले ही एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है, जिसने वैश्विक बाजारों को और भी गहरी अनिश्चितता में धकेल दिया है। UAE ने अपनी सरकारी समाचार एजेंसी WAM के ज़रिए यह घोषणा की। UAE ने कहा, "यह फैसला UAE के दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण और उसकी बदलती ऊर्जा प्रोफ़ाइल को दर्शाता है - जिसमें घरेलू ऊर्जा उत्पादन में तेज़ी से निवेश शामिल है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक ज़िम्मेदार, भरोसेमंद और भविष्योन्मुखी भूमिका निभाने की उसकी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है। यह कदम ऐसे समय में भी आया है जब UAE का सऊदी अरब के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है, खासकर आर्थिक मुद्दों और यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे युद्ध को लेकर। OPEC के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय से जुड़े सदस्यों में से एक होने के नाते, UAE ने पारंपरिक रूप से इस गुट की रणनीतियाँ तय करने में अहम भूमिका निभाई है।

हिमाचल में पंचायत चुनाव का आगाज 50 लाख से अधिक मतदाता

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 का आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को चुनाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग के मुताबिक, पूरे राज्य में पंचायती राज का चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव 26 मई, दूसरे चरण का चुनाव 28 मई और 30 मई को तीसरे चरण का चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची (Himachal Election Commissioner Anil Kumar Khachi) ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी कार्यक्रमों की जानकारी दी है। अनिल कुमार खाची (Anil Kumar Khachi) ने कहा कि ये चुनाव राज्य के सभी 12 जिलों में प्रधान, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों सहित कुल 31,182 पदों के लिए होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि यह चुनावी कार्यक्रम कुल्लू जिले की 4 ग्राम पंचायतों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक वैध है। हालांकि वहां पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव अभी भी आयोजित किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल चुनाव दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग

पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, भवानीपुर समेत कई सीटों पर कांटे की टक्कर।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत बुधवार को 142 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण को लेकर चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। राज्य के 7 जिलों में होने वाली वोटिंग के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के 3.5 लाख से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। इनमें CRPF, SSB, RPF, ITBP और CISF के जवान शामिल हैं। सिर्फ कोलकाता में करीब 35 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि पूरे राज्य में 2550 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं। इसके साथ ही 142 जनरल ऑब्जर्वर और 95 पुलिस ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं।इस बार चुनाव में पहली बार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की भी तैनाती की गई है। पूरे राज्य की निगरानी कोलकाता के सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिसे 7 क्लस्टर में बांटा गया है और हर क्लस्टर की जिम्मेदारी एक नोडल अधिकारी को सौंपी गई है। सभी पोलिंग स्टेशनों के आसपास सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और उनकी लाइव फीड कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 6 हजार से अधिक क्विक रिस्पॉन्स टीमें बनाई गई हैं और संवेदनशील इलाकों में बख्तरबंद वाहनों से गश्त की जा रही है।इस चरण में कुल 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि, इस बार वोटर लिस्ट से नाम कटने का मुद्दा बड़ा बनकर उभरा है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली और नदिया जैसे जिलों में बड़ी संख्या में वोट कम हुए हैं, जिससे करीब 25 सीटों पर चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।कोलकाता की भवानीपुर सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट पर करीब 25 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने का दावा किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। भवानीपुर को 'मिनी इंडिया' कहा जाता है, जहां विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, जिससे यह सीट और भी अहम बन जाती है।

- **नॉर्थ और साउथ 24 परगना जिलों को इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 142 में से 64 सीटें इन्हीं क्षेत्रों में आती हैं। पिछले चुनाव में इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। साउथ 24 परगना में मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा प्रतिशत होने के कारण यहां चुनावी माहौल ज्यादा गर्म है।**

मंगल पांडेय की जगह खाली हुई सीट पर सूर्य कुमार शर्मा

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को बिहार और महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद उपचुनाव एवं द्विवार्षिक चुनाव-2026 के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की. बीजेपी ने बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, महाराष्ट्र में उपचुनाव के लिए डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. बिहार में मंगल पांडेय की जगह खाली हुई सीट पर सूर्य कुमार शर्मा के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया है. इस सीट पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भेजा जाना था. ऐसे में कहीं न कहीं कुशवाहा के लिए यह झटका देने वाली बात है. सूर्य कुमार शर्मा अभी बिहार बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी हैं. वे करीब 40 साल से संगठन में जुड़े रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा के साथ काम कर चुके हैं. वे नितिन नवीन के भी भरोसेमंद माने जाते हैं. भूमिहार जाति से आते हैं और बिहार के अरवल जिले के रहने वाले हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल दरें घोषित

गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आधारभूत परियोजनाओं में से एक है, जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। टोल दरों के निर्धारण के बाद अब इसके संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम पूरा हो गया है।

उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए टोल दरें तय कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा जारी नई दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होंगी। ये दरें प्रति किलोमीटर के आधार पर निर्धारित की गई हैं और दिसंबर 2025 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर तय की गई हैं।जारी दरों के अनुसार, दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर चालकों को प्रति किलोमीटर 1.28 रुपये का टोल देना होगा। वहीं कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन के लिए यह दर 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर रखी गई है। हल्के वाणिज्यिक वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनीबस के लिए 4.05 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है। बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए टोल दर 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। इसके अलावा भारी निर्माण मशीनरी , अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और तीन से छह एक्सल वाले मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 12.60 रुपये प्रति किलोमीटर शुल्क देना होगा। सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज्ड वाहनों के लिए सबसे अधिक 16.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है।यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक, यह दरें एक्सप्रेसवे के संचालन और रखरखाव के खर्च को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। साथ ही भविष्य में महंगाई दर के अनुसार इन टोल दरों में संशोधन भी संभव है।

अमेरिका-ईरान वार्ता को नई उम्मीद

अमेरिका और ईरान ने संकेत दिए हैं कि वे इस्लामाबाद में प्रस्तावित युद्धविराम वार्ता के अगले दौर में हिस्सा ले सकते हैं। दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से पटरी पर लौट सकती है।इससे पहले ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे चरण की शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिससे मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि हालात बिगड़ने पर अमेरिका फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

'e-श्रम साथी' मोबाइल ऐप लॉन्च

छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए एक बड़ा कदम

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मजदूरों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 'e-श्रम साथी' मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य श्रमिकों को घर बैठे रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। यह लॉन्च श्रम विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों में तकनीक के माध्यम से औचक निरीक्षण किए जाएं, ताकि मजदूरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सही तरीके से रक्षा हो सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी योजना का असली असर तभी दिखाई देता है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो। इसके लिए उन्होंने फील्ड स्टाफ को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में श्रमिकों के हित में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें 4 नए लेबर कोड लागू करना भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि मजदूरों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य वातावरण मिल सके। बैठक में श्रम विभाग, श्रम आयुक्त संगठन, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न बोर्डों की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जिला स्तर पर श्रम कार्यालयों को मजबूत करने और श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर भी जोर दिया गया।

यूएई का ओपेक से अलग होने का बड़ा फैसला

1 मई से खत्म होगी सदस्यता, ऊर्जा रणनीति में बड़ा बदलाव

यूएई ने 1 मई से ओपेक छोड़ने का फैसला लिया, जो उसके दीर्घकालिक आर्थिक हितों और ऊर्जा रणनीति से जुड़ा है। सऊदी अरब से तनाव, उत्पादन कोटे की सीमाएं और क्षेत्रीय राजनीतिक मतभेद इसके मुख्य कारण हैं। इससे वैश्विक तेल बाजार और ओपेक प्लस की ताकत पर असर पड़ सकता है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ओपेक टूट गया। यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया। इसको आप यूएस ईरान युद्ध की पहली केजुअल्टी मान सकते हैं। जी हां, यह ताकत थी जो पूरी दुनिया में दरअसल तेल के बाजार को कंट्रोल करती थी और यह ताकत, यह परिवार बिखरने लगा है। क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या कुछ इसकी वजह हैं? 1 मई से आधिकारिक रूप से यूएई ओपेक संगठन का हिस्सा नहीं रहेगा। करीब 10% उत्पादन पर तेल के यूएई का कब्जा था। यूएई का कुल आपूर्ति में योगदान था। लेकिन उससे बड़ी यूएई की पोजीशनिंग, पोशगिंग इस पूरे ग्रुप में थी। साल 2016 में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) ने 10 ऐसे अन्य देशों के साथ साझेदारी की जो तेल का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन ओपेक के सदस्य नहीं थे (इनमें रूस सबसे प्रमुख है)। इन सभी देशों के मिलकर बने इस नए और बड़े समूह को ही 'ओपेक प्लस' (OPEC+) कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितना भी तेल निकाला जाता है, उसका लगभग 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा इसी गठबंधन के नियंत्रण में है। इतनी बड़ी मात्रा में तेल पर नियंत्रण होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल (ऊर्जा) की कीमतें तय करने या उन पर असर डालने में इस समूह की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साल 2016 में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) ने 10 ऐसे अन्य देशों के साथ साझेदारी की जो तेल का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन ओपेक के सदस्य नहीं थे (इनमें रूस सबसे प्रमुख है)। इन सभी देशों के मिलकर बने इस नए और बड़े समूह को ही 'ओपेक प्लस' (OPEC+) कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितना भी तेल निकाला जाता है, उसका लगभग 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा इसी गठबंधन के नियंत्रण में है। इतनी बड़ी मात्रा में तेल पर नियंत्रण होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल (ऊर्जा) की कीमतें तय करने या उन पर असर डालने में इस समूह की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह एक मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) से अलग हो जाएगा। यूएई ने अपनी सरकारी समाचार एजेंसी 'डब्ल्यूएएम' के माध्यम से यह घोषणा की। यूएई ने कहा कि यह निर्णय संयुक्त अरब अमीरात के दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण तथा बदलते ऊर्जा समीकरणों को दर्शाता है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक जिम्मेदार, विश्वसनीय और दूरदर्शी भूमिका निभाने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब यूएई का सऊदी अरब के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर आर्थिक मुद्दों और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन में जारी युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति है। यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन उसे लंबे समय से यह शिकायत थी कि ओपेक के सख्त नियमों और कोटे की वजह से वह अपनी क्षमता के मुताबिक तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है (यानी तेल नहीं बेच पा रहा है)। ओपेक छोड़ने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में ईरान के हमलों के दौरान बाकी अरब देशों ने यूएई को सैन्य और राजनीतिक समर्थन नहीं दिया था, जिसकी यूएई ने कड़ी आलोचना भी की थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि समूह से बाहर निकलने का यह फैसला उनकी 'लंबी अवधि की रणनीतिक और आर्थिक सोच' का हिस्सा है। इससे उन्हें बाजार के बदलते हालात के हिसाब से तुरंत और स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में ज्यादा आज़ादी मिलेगी।

भारत को मई में मिलेगा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत को मई के मध्य तक रूस से अपना चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। यह सिस्टम, जिसे पिछले हफ्ते भारतीय वायु सेना (IAF) के अधिकारियों द्वारा प्री-डिस्पैच निरीक्षण के बाद भेजा गया था, उम्मीद है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की मिसाइल रक्षा स्थिति को मज़बूत करने के लिए राजस्थान सेक्टर में तैनात किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह डिलीवरी 'ऑपरेशन सिंदूर' की बरसी की पूर्व संध्या पर हुई है, जिसके दौरान S-400 सिस्टम का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत पांचवां और आख़िरी सिस्टम इस साल नवंबर में भेजे जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिस्टम ने संघर्ष के दौरान ज़बरदस्त ऑपरेशनल क्षमता दिखाई; बताया जाता है कि भारत ने 11 लंबी दूरी की S-400 मिसाइलें दागीं, जिन्होंने कई हवाई ख़तरों को बेअसर कर दिया, जिनमें लड़ाकू विमान, हवाई चेतावनी प्रणाली और परिवहन विमान शामिल थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने पहले ही पाँच अतिरिक्त S-400 प्रणालियों के अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में हवाई ख़तरों को निशाना बनाने में सक्षम हैं, जिसमें पाकिस्तान में सिंधु नदी के पूर्व के इलाके भी शामिल हैं। इसके साथ ही, भारत 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों के स्टॉक को फिर से भरने और एक रिज़र्व इन्वेंट्री बनाने के लिए 280 छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलें ख़रीदने की योजना बना रहा है।

जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों से एयरलाइन इंडस्ट्री पर संकट

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री ने सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की है, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी से उनके कामकाज पर दबाव पड़ रहा है और लागत बढ़ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA)—जो एयर इंडिया, IndiGo और SpiceJet जैसी एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने चेतावनी दी है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की आसमान छूती कीमतों के कारण यह सेक्टर 'बेहद तनाव' का सामना कर रहा है। उद्योग संगठन ने कहा कि मौजूदा लागत का माहौल कई मार्गों को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना रहा है, और यदि कीमतें ऊँची बनी रहती हैं, तो एयरलाइनों को अपने परिचालन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस चिंता की मुख्य वजह ATF की कीमतों में आई तेज़ी है। हाल के बदलावों में, पश्चिम एशिया में तनाव के चलते ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए, ATF की कीमतें 2 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के पार चली गई हैं। इंडस्ट्री के मुताबिक, एविएशन फ्यूल, जो आम तौर पर एयरलाइन के ख़र्चों का लगभग 30-40% होता है, अब बढ़कर ऑपरेटिंग ख़र्चों का 55-60% तक हो गया है। इस बदलाव ने मुनाफ़े के मार्जिन को काफ़ी कम कर दिया है। अपने पत्र में FIA ने बताया कि एयरलाइंस इस बढ़ोतरी को झेलने में मुश्किल महसूस कर रही हैं, ख़ासकर इंटरनेशनल रूट्स पर, जहाँ फ्यूल की लागत ज़्यादा होती है और कीमतों में बदलाव की गुंजाइश कम होती है।

ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान 'पतन की स्थिति' में

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान "पतन की स्थिति" में है, और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि तेहरान ने व्हाइट हाउस से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने का अनुरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया कि ईरान ने यह संदेश किस तरह भेजा था। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि तेहरान नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने अभी-अभी हमें बताया है कि वे 'पूरी तरह से ढहने की स्थिति' में हैं। वे चाहते हैं कि हम 'होर्मुज जलडमरूमध्य खोल दें,' जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वे अपनी नेतृत्व की स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह ताज़ा पोस्ट उन कई दावों में से एक है जो ट्रंप ने पिछले दो महीनों में होरमुज़ जलडमरूमध्य को लेकर किए हैं, जबकि नाकाबंदी ख़त्म करने की कोशिशों के नतीजे बहुत कम निकले हैं। अमेरिका और इज़रायल के बीच हफ़्तों तक चली लड़ाई के बाद भी, होर्मुज़ जलडमरूमध्य जो वैश्विक व्यापार का एक अहम और संकरा रास्ता

है। समुद्री यातायात के लिए बंद ही है। ईरान ने अपनी नौसेना के ज़रिए नाकेबंदी कर दी है और इस संकरे रास्ते में 6,000 बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अमेरिका ने भी इस जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों पर नाकेबंदी लगाने का दावा किया है। ईरान ने एक अंतरिम समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत वाशिंगटन द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ख़त्म करने के बदले में स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को फिर से खोल दिया जाएगा। हालाँकि, दोनों देशों के बीच नाकेबंदी और इस क्षेत्र में चल रहे बड़े संघर्ष को ख़त्म करने के लिए किसी अंतरिम समझौते पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में बढ़ती उत्तर कोरिया की भूमिका

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

उत्तरी कोरिया ने यूक्रेन में रूस के युद्ध में मदद के लिए हज़ारों हथियार और सैनिक भेजे हैं; इनके बीच, उसके सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी जान देने की ख़बरें विशेष रूप से चौंकाने वाली हैं। ब्लूमबर्ग ने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने रविवार को उन सैनिकों की तारीफ़ की, जिन्होंने कथित तौर पर युद्ध की रणनीति के तहत, यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की लड़ाई में पकड़े जाने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। किम ने कहा कि उन्होंने "महान सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मौत" पाई। यह रणनीति, जिसमें सैनिक पकड़े जाने के बजाय युद्ध के मैदान में अपनी जान दे देते हैं, किम की टिप्पणियों के बाद चर्चा में आ गई है। ये टिप्पणियाँ उन पिछली रिपोर्टों के बाद आई

हैं जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन में मौजूद उत्तर कोरियाई सैनिकों को हर हाल में पकड़े जाने से बचने का निर्देश दिया गया था, जिसमें अपनी जान देना भी शामिल था। ये दावे यूक्रेनी ख़ुफ़िया एजेंसियों की रिपोर्टों और पकड़े गए एक उत्तर कोरियाई सैनिक की गवाही पर आधारित थे। किम ने एक भाषण में कहा कि वे नायक जिन्होंने महान सम्मान की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के ख़ुद को उड़ाने या आत्मघाती हमले का रास्ता चुना।" उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने किसी भी तरह के मुआवज़े की उम्मीद नहीं की, हालाँकि उन्होंने असाधारण वीरता दिखाई। उन्होंने एक वीरगति पाई।

संपादक की कलम से

देश की अर्थव्यवस्था के विकास के दावों के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी वास्तव में इस विकास का लाभ महसूस कर पा रहा है? बढ़ती महंगाई ने इस प्रश्न को और भी गंभीर बना दिया है। रोजमर्रा की जरूरतों—जैसे खाद्य पदार्थ, पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और बिजली—की कीमतों में लगातार वृद्धि ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है। महंगाई केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह सीधे लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। जब सब्जियों, दालों और अनाज की कीमतें बढ़ती हैं, तो परिवारों को अपने बजट में कटौती करनी पड़ती है। कई बार उन्हें अपनी आवश्यक जरूरतों को भी सीमित करना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है, जिनकी आय स्थिर है या बहुत कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिससे हर वस्तु महंगी हो जाती है। यही कारण है कि जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं, तो बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है।सरकार द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि सब्सिडी देना, आयात-निर्यात नीतियों में बदलाव करना और बाजार पर निगरानी रखना। लेकिन कई बार ये प्रयास पर्याप्त नहीं होते। जरूरत इस बात की है कि नीतियां केवल अल्पकालिक समाधान न दें, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित करें।इसके साथ ही, जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी समस्याएं भी महंगाई को बढ़ावा देती हैं। जब कुछ लोग कृत्रिम रूप से वस्तुओं की कमी पैदा करते हैं, तो कीमतें और बढ़ जाती हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होती है ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। महंगाई का एक सामाजिक प्रभाव भी है। यह न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाती है, बल्कि समाज में असंतोष भी पैदा करती है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ रहा है, तो उनका विश्वास व्यवस्था पर कम होने लगता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार, उद्योग और आम जनता—सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। सरकार को जहां एक ओर मजबूत आर्थिक नीतियां बनानी होंगी, वहीं उद्योगों को भी कीमतों को संतुलित रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी। आम जनता को भी अपने खर्चों में संतुलन बनाना होगा और अनावश्यक खर्च से बचना होगा। अंततः, यह समझना जरूरी है कि महंगाई केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर देश के विकास और सामाजिक संतुलन दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और ठोस समाधान निकाले जाएं।

गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत

सभी 15 नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा

गुजरात निकाय चुनावों में भाजपा ने सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज करते हुए 1044 में से 856 सीटें हासिल कीं। अहमदाबाद और सूरत में शानदार प्रदर्शन रहा, जबकि आप और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। ये नतीजे राज्य में भाजपा की मजबूत स्थिति और विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ते मनोबल को दिखाते हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुए निकाय चुनावों ने राज्य की राजनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह संकेत दे दिया है कि राज्य में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। चुनाव परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व पर कायम है। निकाय चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य के सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज की। यह जीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि व्यापक जनसमर्थन का प्रमाण भी है। पार्टी ने हर नगर निगम में 50 प्रतिशत से अधिक सीटें हासिल कीं। कुल 1044 सीटों में से 856 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा। यह परिणाम दिखाता है कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में भाजपा ने 192 में से 158 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की। यह जीत न केवल संगठन की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी की लोकप्रियता को भी साबित करती है। अहमदाबाद नगर निगम के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि भाजपा का शहरी वोट बैंक अभी भी मजबूत है और विपक्ष यहां प्रभावी चुनौती देने में असफल रहा।सूरत में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 127 में से 115 सीटों पर कब्जा जमाया। यह परिणाम विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले चुनाव में 27 सीटें जीती थीं, इस बार केवल 4 सीटों तक सिमट गई। वहीं कांग्रेस की स्थिति भी बेहद कमजोर रही और उसे सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी दल अपनी पकड़ बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं। सूरत में आम आदमी पार्टी को एक और झटका तब लगा जब उसकी वरिष्ठ नेता पायल सकारिया अपनी सीट हार गईं। यह हार केवल एक सीट का नुकसान नहीं, बल्कि संगठनात्मक कमजोरी का संकेत भी है। इससे यह साफ है कि पार्टी भाजपा के सामने मजबूती से खड़ी नहीं हो सकी। भाजपा की इस बड़ी जीत के पीछे पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत को अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं ने इस जीत का श्रेय शीर्ष नेतृत्व को दिया है। उनका कहना है कि देश की बढ़ती वैश्विक साख और मजबूत आंतरिक सुरक्षा ने जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। साथ ही, पार्टी कार्यकर्ता हर स्तर पर बेहतर शासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।चुनावों में लगभग 66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने भी चुनावी माहौल को और अधिक सक्रिय बनाया।कुल मिलाकर, गुजरात के निकाय चुनावों के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत है। यह जीत आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का मनोबल बढ़ाएगी, जबकि विपक्षी दलों के लिए यह संकेत है कि उन्हें अपनी रणनीति और संगठन दोनों को मजबूत करने की जरूरत है।

नितिन गडकरी ने परियोजनाओं में देरी पर उठाए सवाल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

नई दिल्ली में आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन और अचीवर्स अवार्ड्स 2026 में देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। Associated Chambers of Commerce and Industry of India यानी एसोचैम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने परियोजनाओं में देरी तथा बढ़ती लागत के कारणों पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि निर्णय लेने में देरी, कमजोर योजना और जवाबदेही की कमी ही परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के मुख्य कारण हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि अधिग्रहण जैसी छोटी दिखने वाली समस्याएं और अनुमति मिलने में देरी भी बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इन बुनियादी समस्याओं को समय रहते हल किया जाए तो परियोजनाओं की लागत और समय दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। गडकरी ने गुणवत्ता के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कई बार ठेकेदार घटिया काम करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें काली सूची में डाला जाना चाहिए। उनके अनुसार केवल काम की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्ता को समान महत्व देना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया के कारण किसी भी छोटी खामी को तुरंत उजागर किया जा सकता है, इसलिए पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। उन्होंने तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि निर्माण लागत कम करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कचरे से ऊर्जा उत्पादन, नए निर्माण सामग्री का उपयोग और नवाचार को अपनाना भविष्य के लिए आवश्यक बताया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्णता प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन निरंतर सुधार के प्रयास किए जा सकते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वह मिलकर अपने कार्यों की समीक्षा करें और सुधार के उपाय तलाशें। उनके अनुसार नीति निर्धारकों को सार्थक सुझाव देने के लिए यह प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्य में कमियां हो सकती हैं, लेकिन दूसरों के सुझावों को अपनाकर सुधार संभव है।

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सुरक्षा सख्त, एनआईए की तैनाती

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दूसरे चरण से पहले, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को तैनात किया है। चुनाव अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ऐसा यह पक्का करने के लिए किया गया है कि बदमाश वोटिंग में रुकावट डालने और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए 'बमों का इस्तेमाल न करें'। यह कदम चुनाव वाले राज्य में देसी बम मिलने और एक छोटे धमाके की खबरों के बाद उठाया गया है। वोटिंग का पहला चरण 23 अप्रैल को हुआ था, जबकि दूसरा चरण बुधवार को होना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि आयोग वोटिंग के दिन या उसके बाद होने वाली किसी भी हिंसा को रोकने और यह पक्का करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है कि वोटर बिना किसी डर के अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। 26 अप्रैल को, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले के भांगर में एक व्यक्ति के घर से कम से कम 79 देसी बम बरामद किए। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस (TMC) का कार्यकर्ता है। पुलिस ने बताया कि रफ़ीकुल इस्लाम के घर पर तलाशी अभियान के दौरान ये विस्फोटक ज़ब्त किए गए। यह तलाशी अभियान खास खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राज्य में 79 देसी बमों की बरामदगी की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने देर रात जारी एक बयान में बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए, आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने रविवार को एक मामला दर्ज किया। यह मामला मूल रूप से शनिवार को कोलकाता के भांगर डिवीज़न के उत्तर काशी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। एजेंसी ने अब इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। प्रवक्ता ने कहा, "यह मामला कोलकाता पुलिस द्वारा 79 देसी बमों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से जुड़ा है। इन चीज़ों को एक जगह पर जमा करके रखा गया था, जिससे इंसानी जान और माल को खतरा पैदा हो गया था।

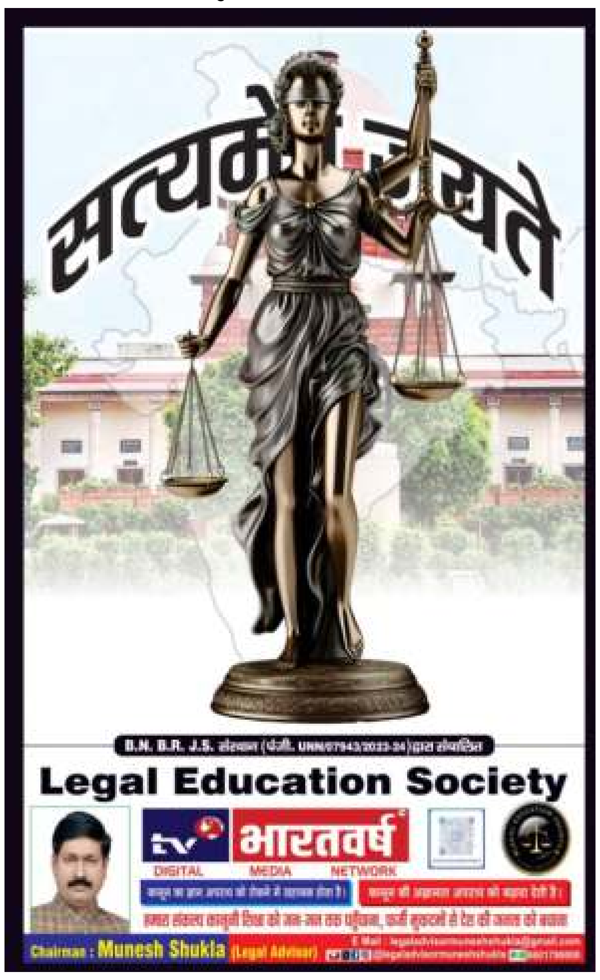

भारतीय रिजर्व बैंक का U-Turn!

सख्ती के बाद बाजार को खुली छूट

भारतीय वित्तीय बाजार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए पहले लागू किए गए कुछ कड़े नियमों में अब राहत देने का फैसला किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बाजार में उतार-चढ़ाव को लेकर निवेशकों और कारोबारियों के बीच चिंता बनी हुई थी। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा कारोबारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है, जो विशेष रूप से ऑफशोर नॉन-डिलीवेरेबल फॉरवर्ड (NDF) बाजार से जुड़े थे। यह वह बाजार होता है जहां वास्तविक मुद्रा का लेन-देन नहीं होता, बल्कि भविष्य की विनिमय दरों पर सौदे तय किए जाते हैं। इस तरह के सौदे अक्सर मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी को बढ़ाते हैं और विनिमय दरों पर दबाव डालते हैं। दरअसल, मार्च के अंतिम दिनों में आरबीआई ने रुपये में आई तेज गिरावट को थामने के लिए कई सख्त कदम उठाए थे। उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई थीं, जिसका एक बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव था। इस भू-राजनीतिक स्थिति का सीधा असर भारतीय रुपये पर पड़ा और यह अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 95.21 प्रति डॉलर तक गिर गया था। इन परिस्थितियों में आरबीआई ने बैंकों और विदेशी मुद्रा कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी और ऑफशोर बाजार में सट्टेबाजी को सीमित करने के लिए प्रतिबंध लगाए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल तक बैंकों ने करीब 40 अरब डॉलर के सट्टेबाजी वाले सौदों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद रुपये में कुछ स्थिरता आई और यह अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर संभलने लगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में स्पष्ट किया कि मार्च में उठाए गए सख्त कदम अस्थायी थे और उनका उद्देश्य केवल बाजार में बढ़ती अस्थिरता को नियंत्रित करना था। उन्होंने कहा कि अत्यधिक सट्टेबाजी के कारण मुद्रा बाजार में असंतुलन पैदा हो गया था, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक था। केंद्रीय बैंक ने यह भी दोहराया है कि वह भारतीय रुपये को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने और वित्तीय बाजार को अधिक गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब प्रतिबंधों में ढील देने से बाजार में तरलता बढ़ेगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि आरबीआई को सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि वैश्विक बाजार अब भी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक स्थितियां रुपये की चाल को प्रभावित कर सकती हैं। कुल मिलाकर, आरबीआई का यह कदम संतुलित रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें एक ओर बाजार की स्थिरता दी गई है और दूसरी ओर कारोबार और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि यह फैसला रुपये को कितनी मजबूती प्रदान करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाता है।

लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ी राहत, जोश इंग्लिस की वापसी तय

आईपीएल 2026 में संघर्ष कर रही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। टीम के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों में शामिल ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस जल्द ही टीम से जुड़ने वाले हैं, जिससे लखनऊ की बल्लेबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 31 वर्षीय इंग्लिस टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के चलते शुरुआती मुकाबलों से नाम वापस ले लिया था। उनकी शादी 18 अप्रैल को संपन्न हुई और इसके बाद उन्होंने थोड़े समय का ब्रेक लिया। अब खबर है कि वे जल्द ही भारत पहुंचकर टीम के साथ जुड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंग्लिस 4 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले लखनऊ की टीम में शामिल हो जाएंगे। इंग्लिस की वापसी ऐसे समय में हो रही है जब लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार जीत की सख्त जरूरत है। टीम का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आने वाले मैच बेहद अहम हैं। ऐसे में एक अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज का जुड़ना टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। गौरतलब है कि लखनऊ फ्रेंचाइजी ने जोश इंग्लिस को 8.6 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत में अपनी टीम में शामिल किया था। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग क्षमता को देखते हुए टीम मैनेजमेंट को उनसे काफी उम्मीदें हैं। यदि वे तय समय पर टीम से जुड़ते हैं, तो लीग स्टेज के आखिरी छह मुकाबलों में उनका योगदान निर्णायक हो सकता है।

भुवनेश्वर कुमार के सिर सजी पर्पल कैप

विराट कोहली दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे। जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और अपना अनुभव शेयर किया। इस दौरान उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए जीवन में आगे बढ़ने, सपने पूरे करने की सीख दी। कोहली ने यहां क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया और इसी दौरान संबोधन में बच्चों की जिंदगी में कुछ कर गुजरने का रास्ता भी बताया। कोहली इस समय आईपीएल 2026 में खेल रहे हैं। उनकी टीम आरसीबी ने सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को मात दी। इस मैच के दौरान कोहली ने टी20 में अपने 9000 रन पूरे किए हैं। बच्चों को संबोधित करते हुए कोहली ने अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि कैसे उन्होंने बहुत कम उम्र में क्रिकेट को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। कोहली ने कहा कि, मुझे यहां बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं स्कूल में बोलने का आदी नहीं हूं इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा अजीब होने वाला है क्योंकि मैं काफी पहले ही स्कूल सेट अप से दूर चला गया था। जिसका कारण क्रिकेट था और मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। कोहली ने कहा कि, आप बच्चे इस समय जिस दौर में हैं और जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उसका हिस्सा मैं भी रह चुका हूं। मैं सिर्फ अपना अनुभव बता सकता हूं कि कैसे मेरे शुरुआती जीवन में मेरा फोकस और मेरी प्राथमिकता बदल गई थी। इस दौरान कोहली ने कहा कि बच्चों को अपने आस-पास के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बस ये कहना चाहता हूं कि स्कूल ऐसी जगह है जहां आप सीखने आते हैं आगे बढ़ने आते हैं और आप बेहतर इंसान बनते हैं। पहले आपके पास जो वातारवण है उसका सम्मान कीजिए, आपके टीचर्स जो लोग आपको सिखा रहे हैं उनका सम्मान कीजिए। वह आपको अपने जीवन का हिस्सा दे रहे हैं। उन लोगों को वो सम्मान, वो फोकस और प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसके वो हकदार हैं।

टी20 वर्ल्ड कप में फिक्सिंग का साया!

कनाडा मैच पर बड़ा खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले को लेकर मैच फिक्सिंग के आरोप सामने आए हैं, जिनमें कथित तौर पर आपराधिक नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का नाम इस मामले में सामने आया है। आरोप है कि उनका संबंध जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच जारी है। कनाडा के सार्वजनिक प्रसारक की रिपोर्ट में एक सनसनीखेज घटना का जिक्र किया गया है। बताया गया कि जुलाई 2025 में ब्रिटिश कोलंबिया के एक रेस्टोरेंट में कुछ क्रिकेटर डिनर कर रहे थे, तभी कथित तौर पर बिश्नोई गैंग से जुड़े लोग वहां पहुंचे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने कनाडा के एक खिलाड़ी को धमकी दी कि यदि दिलप्रीत बाजवा और एक अन्य खिलाड़ी को टीम में आगे बढ़ाने में मदद नहीं की गई, तो उनके और उनके परिवार के लिए गंभीर परिणाम

हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है, तो यह खेल की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए बड़ा झटका होगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट करता है कि आपराधिक तत्व खेलों में दखल देने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल संबंधित क्रिकेट बोर्ड और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी हुई हैं। यह देखना अहम होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की भूमिका साबित होती है।

चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका, आयुष म्हात्रे पूरे सीजन से बाहर

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही खराब फॉर्म से जूझ रही टीम को अब एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय म्हात्रे के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। मेडिकल जांच के बाद यह साफ हुआ कि उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 6 से 8 हफ्तों का समय लगेगा, जिसके चलते वह आईपीएल 2026 के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यह खबर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि टीम पहले ही खराब प्रदर्शन से गुजर रही है। अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में टीम को केवल 2 में जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को जल्द वापसी करनी होगी।आयुष म्हात्रे इस सीजन में टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे थे। उन्होंने 6 मैचों की 6 पारियों में 33.50 की औसत और 177.87 के शानदार स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक भी निकले, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 73 रन रहा। मौजूदा सीजन में वह चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। टीम पहले ही अनुभवी खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर जूझ रही थी और अब युवा बल्लेबाज के बाहर होने से बल्लेबाजी क्रम और कमजोर पड़ सकता है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती

संतुलन बनाने और नए विकल्प तलाशने की होगी। आईपीएल जैसे लंबे और प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में चोटें टीम के प्रदर्शन पर बड़ा असर डालती हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स इस झटके से कैसे उबरती है और आने वाले मुकाबलों में किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है।

ऑस्ट्रेलिया में एक दिन की कमाई 40 हजार

विदेश में मिलता है मेहनत का सही मोल?

आजकल सोशल मीडिया पर विदेश में काम करने और वहां की कमाई को लेकर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं.

इन्हीं में से एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति ने अपनी कमाई के बारे में खुलकर बात की है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच विदेश में काम करने को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. इस वीडियो में रविंद्र नाम के एक व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

कोलकाता के शख्स ने लता के गाने पर दी ऐसी परफॉर्मेंस, रो पड़ा सोशल मीडिया

जुबां खामोश, पर बोल उठीं आंखें

आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसमें कोलकाता के रहने वाले एक व्यक्ति ने बिना ज्यादा बोले, सिर्फ अपनी आंखों के जरिए गहरी भावनाएं व्यक्त कर दीं. इस वायरल वीडियो में कोलकाता के बिभु नाम के एक शख्स ने मशहूर पुराने गीत हम तेरे प्यार में सारा आलम पर लिप-सिंक किया है.

यह गीत अपनी भावनाओं और गहराई के लिए पहले से ही लोगों के दिलों में खास जगह रखता है. इस गाने को महान गायिका लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से अमर बना दिया था. इस वीडियो में बिभु ने जिस अंदाज में इसे प्रस्तुत किया, उसने लोगों को हैरान कर दिया.

वह कैमरे के सामने शांत बैठकर बिना किसी बड़े एक्सप्रेशन या ओवर एक्टिंग के केवल अपनी आंखों और हल्की-फुल्के एक्सप्रेशन के जरिए गाने की हर लाइन को महसूस कराते हैं. बताया जा रहा है कि यह गाना एक कवर वर्जन है, जिसे एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. बिभु ने इसी कवर पर लिप-सिंक करते हुए इस गाने को गाया है. उनकी आंखों में नमी, चेहरे की सादगी और भावनाओं की गहराई इतनी साफ दिखाई देती है कि देखने वाला खुद भावुक हो जाता है. यह गाना साल 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का है.

14 साल में तीन गुना बढ़ी मुस्लिम आबादी

जापान में 'दक्षिणपंथ' की नई लहर!

जापान में इन दिनों मुस्लिम विरोधी लहर देखने को मिल रही है. पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मौकों पर वहां की स्थानीय जनभावना में बढ़ती मुस्लिम आबादी के प्रति विरोध का भाव दिखा है. इसकी झलक वहां की चुनी सरकार में भी नजर आई है.

- जापान में मस्जिद निर्माण और हलाल भोजन पर रार
- देश में पहले 4 मस्जिद थीं, अब हैं करीब 150!

जापान में आम चुनाव के दौरान काफी मुस्लिम विरोधी मुद्दे उठे. जगह-जगह मस्जिद निर्माण और कब्रिस्तानों के लिए प्रस्तावित जगह का विरोध हुआ.

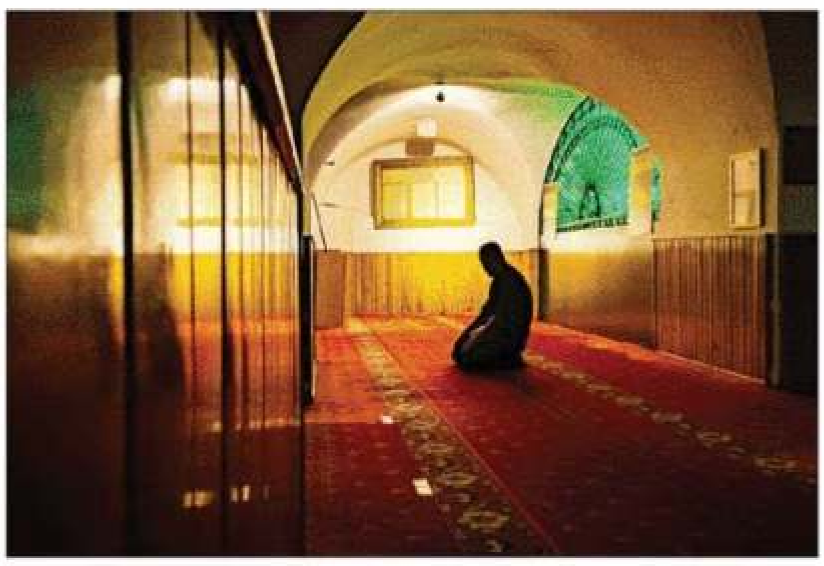

जापान में बढ़ रही हैं मुस्लिम विरोधी जनभावनाएं (Photo - Pexels)

इन दिनों जापान में हर जगह मुस्लिम विरोधी लहर देखने को मिल रही है.

वहां की नई सरकार भी इससे अछूती नहीं है. क्योंकि, उनकी नीतियां में कहीं न कहीं प्रवासियों और विदेशी आबादी के प्रति सख्ती दिखाई दे रही है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर वहां ऐसा क्या बदलाव हो रहा है कि इस छोटे से देश में भी मुस्लिम विरोधी भागवनाएं बढ़ती जा रही हैं.

टोक्यो के पास योकोहामा में चुनाव के दौरान वहां प्रस्तावित मस्जिद को एक प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की गई. साथ ही उन स्थानीय लोगों की भी जापानी आलोचना करते दिखे, जो कह रहे हैं कि मस्जिद का विरोध विदेशियों के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रही है.

विदेशियों को लेकर सख्त हैं नई प्रधानमंत्री

वह आव्रजन और विदेशियों पर सख्त नीतियों के लिए भी जोर दे रही हैं. यह बढ़ती हुई धुर दक्षिणपंथी आबादी के साथ मेल खाता है, जिसने एंटी ग्लोबलिस्ट पार्टी सैनसेइटो के बढ़ते प्रभाव का समर्थन किया है, जो कहती है कि जापान की घटती आबादी के सोल्यूशन के रूप में विदेशी श्रम को बढ़ावा देने वाली एलडीपी की नीति जापानी समुदायों को असुरक्षित बना रही है और सांस्कृतिक टकराव पैदा कर रही है.

रोल्स-रॉयस में 'चाय' बेचने का तरीका वायरल

कभी कोई अजीबोगरीब स्टंट, तो कभी कोई अलग तरह का बिजनेस आइडिया लोगों का ध्यान खींच लेता है. इसी कड़ी में अब एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने लग्जरी रोल्स-रॉयस में शाही चाय बेचने का अनोखा एक्सपेरिमेंट किया. यह आइडिया जितना अलग है, उतना ही लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन गया है. इस एक्सपेरिमेंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर @delux-ebhaiyaji नाम के यूजर ने शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

10 साल के राहिल देशमुख की धमाकेदार एंट्री, 'राजा शिवाजी' में दिखा जलवा

मराठी सिनेमा और बॉलीवुड में एक नई स्टार किड की एंट्री होने जा रही है, और इस बार चर्चा में हैं रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख के बेटे राहिल देशमुख। 20 अप्रैल को रिलीज हुए ऐतिहासिक ड्रामा राजा शिवाजी के ट्रेलर ने जहां अपनी भव्यता से दर्शकों को प्रभावित किया, वहीं राहिल की झलक ने इसे और खास बना दिया है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत एक भावनात्मक और दमदार दृश्य से होती है, जिसमें 10 वर्षीय राहिल देशमुख युवा छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में नजर आते हैं। इस सीन में वह "स्वराज" के विचार को व्यक्त करते दिखाई देते हैं। यह दृश्य धीरे-धीरे बड़े शिवाजी के रूप में ट्रांजिशन करता है, जिसे खुद रितेश देशमुख निभा रहे हैं। इस तरह पिता-पुत्र की यह जोड़ी एक ही किरदार के दो अलग-अलग चरणों को जीवंत करती दिखेगी। फिल्म की टैगलाइन—"उस धरती के लिए जिसने योद्धाओं को गढ़ा... उस विश्वास के लिए जो कभी नहीं डिगा..."—पहले ही दर्शकों में उत्साह जगा चुकी है। 'राजा शिवाजी' को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके स्वराज के सपने को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जा रहा है। स्टार कास्ट की बात करें तो यह फिल्म एक मल्टीस्टारर प्रोजेक्ट है। रितेश देशमुख के साथ संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और विद्या बालन जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। इसके अलावा महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। वहीं जेनेलिया देशमुख भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियोज़ के सहयोग से किया गया है, जबकि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी ज्योति देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने 'मुंबई फिल्म कंपनी' के बैनर तले संभाली है। फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी अजय-अतुल ने तैयार किया है, जो पहले भी ऐतिहासिक और भव्य फिल्मों में अपने संगीत से जान डाल चुके हैं।'राजा शिवाजी' 1 मई को मराठी, हिंदी और तेलुगू भाषाओं में दुनियाभर के

सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि इसकी रिलीज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर हो रही है, जो इस फिल्म के विषय और भावना के साथ गहराई से जुड़ती है। कुल मिलाकर, 'राजा शिवाजी' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास, भावनाओं और नई पीढ़ी के टैलेंट का संगम बनकर सामने आ रही है—जहां राहिल देशमुख की शुरुआत पर सबकी नजरें टिकी हैं।

यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियों का ऐलान

निष्पक्ष प्रक्रिया से युवाओं को मिलेगा मौका

योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की।उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी, जिसमें सिफारिश या पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी।सीएम ने पिछले 9 वर्षों में 2.20 लाख से अधिक भर्तियों और पुलिस ढांचे में बड़े सुधारों को भी गिनाया।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ में ऐलान किया कि इस साल यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा- होमगार्ड, पुलिस और दरोगा के पदों पर भर्ती होगी। सीएम ने इस दौरान पुलिस विभाग में 936 रेडियो ऑपरेटर को जॉइनिंग लेटर बांटे। उनके साथ फोटो खिंचवाई। सीएम ने कहा- पिछले 9 साल में 2 लाख 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती निष्पक्ष तरीके से की गई, जो एक रिकॉर्ड है। बहुत सारे राज्यों की पुलिस बल की संख्या 2.20 लाख नहीं होगी। 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया गया। सीएम ने कहा- अभी परसों ही 60 हजार सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई। यानी एक साथ 60 हजार सिपाही यूपी पुलिस का हिस्सा बने, जो अब फील्ड में ड्यूटी करेंगे। आपको देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का हिस्सा बनने और उसकी दूरसंचार शाखा के माध्यम से 25 करोड़ की आबादी की सेवा करने का मौका मिला है। इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि आप में से किसी को भी सिफारिश कराने की जरूरत नहीं पड़ी। न कोई सिफारिश, न कोई पैसा। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई। परिणाम हम सबके सामने है। योगी ने कहा- हमारा उद्देश्य एक ही है। हर नौजवान जो योग्य और क्षमतावान है, पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए अच्छा अवसर पुलिस भर्ती बोर्ड उपलब्ध कराएगा। 2017 से पहले 10 ऐसे जिले थे, जहां पुलिस लाइन ही नहीं थी। कई थाने ऐसे थे, जिनके पास अपने भवन नहीं थे। पुलिस को सामान्य सुविधाओं का अभाव था। बैरक नहीं थीं। आज खपरैल की बैरकों की जगह हाईराइज इमारतें बन चुकी हैं। मॉडल थाने बन रहे हैं। नए-नए फायर स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ का गठन हुआ। एसडीआरएफ का गठन हुआ है। तीन नई महिला पुलिस बटालियन भी गठित की गई हैं। योगी ने कहा- पुलिस प्रदेश को गुंडा-मुक्त, दंगा-मुक्त और माफिया-मुक्त ही नहीं बना रही है, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस का बड़ा योगदान है, क्योंकि कानून का राज विकास की पहली गारंटी होता है। कानून के इस माहौल में ही बड़े निवेशक यूपी में निवेश कर रहे हैं। यह सब दिखाता है कि जब करने की इच्छाशक्ति होती है, तो परिणाम अपने आप सामने आते हैं। पुलिस बल से जुड़े हर कार्मिक को खुद को हमेशा फिट रखना जरूरी है। जब आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, तो मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। सीएम ने कहा- कुछ अभ्यर्थियों ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अपनी सक्सेस स्टोरी साझा कीं। उनकी कहानियां बताती हैं कि वे चाहते थे कि उनकी भर्ती पूरी तरह ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हो। यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई है। ऐसे में अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसी नीयत के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यह याद रखना जरूरी है कि जब हर भारतीय नागरिक अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करता है, तभी विकसित भारत का सपना साकार होता है। किसी जाति, मजहब या व्यक्तिगत स्वार्थ का अहंकार राष्ट्र और राज्य से बड़ा नहीं हो सकता।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब 19 मई मिली तारीख

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक न हो पाने के मामले मेंअपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने पर अवमानना की कार्यवाही चलाए जाने की मांग की गई है। याचिका में 4 फरवरी 2026 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया था कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा और संबंधित कानून के तहत इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से आए इस जवाब के आधार पर हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया था। मौजूदा अवमानना याचिका में इसी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक उक्त आयोग का गठन नहीं किया गया, जो कोर्ट की अवमानना की परिधि में आता है।

ओपी राजभर ने कहा ग्राम पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने पर प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। हम खुद इसके समर्थक है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट आदेश देगी तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चुनाव न होने की स्थिति में वह पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसे लागू कराने की कोशिश करेंगे।पंचायती राज मंत्री मंगलवार को पंचायती राज निदेशालय में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय विशेष कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाया गया है। ऐसे में मजबूत प्रस्ताव तैयार किया जाए। दरअसल, कुछ ब्लॉक प्रमुखों द्वारा चुनाव न होने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर नारेबाजी और हंगामा करते हुए कहा कि हमें अपनी मांगें पूरी कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। विभाग के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह व संरक्षक जगमोहन सिंह यादव ने चुनाव न होने की स्थिति में पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाने की मांग रखी। वहीं हर ब्लॉक पर एक सरकारी वाहन, एक करोड़ का बीमा, ब्लॉक प्रमुखों को जिलों में मुख्यमंत्री व मंत्री के कार्यक्रमों में आमंत्रित करने की मांग भी की। प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनिल कुमार ने आश्वासन दिया कि वह

सभी जरूरी मांगें पूरी करेंगे। कार्यशाला में प्रमुख सचिव अनिल कुमार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निदेशक गुंजन द्विवेदी, संयुक्त निदेशक एसएन सिंह, उप्र ब्लॉक प्रमुख संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशवंत सिंह, महामंत्री त्रिपुर मिश्रा आदि मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि जल्द ब्लॉक प्रमुखों की विकास निधि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी। ब्लॉक कार्यालयों में एडीओ पंचायत के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र पंचायत प्रमुख पंचायती राज व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं। मजबूत कार्ययोजना, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी के माध्यम से ही समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रशासनिक समन्वय को सशक्त करने के सत्र भी आयोजित किए गए।

राहुल गांधी की नागरिकता नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष माथुर सुनवाई करेंगे

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अब न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ सुनवाई करेगी। मंगलवार को यह मामला न्यायमूर्ति मनीष माथुर के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने कोर्ट से मामले में आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने याची के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की है। कर्नाटक में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाते हुए एफ आई आर दर्ज करने की मांग की है। पहले, उनकी याचिका लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत से खारिज हुई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के पास उन्होंने मौजूदा याचिका दाखिल की थी। इसी 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने और मामले की जांच कराने का मौखिक आदेश राज्य सरकार को दिया था। अगले ही दिन आए आदेश में अपना फैसला बदलते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इसको लेकर कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले थे। हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में जज का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद नाराज होकर 20 अप्रैल को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस केस से खुद को अलग कर लिया था। याची शिशिर ने बताया कि इसी मामले से संबंधित एक अन्य याचिका भी उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल की है, जिसपर अगले सप्ताह सुनवाई की संभावना है।

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में खड़ी बस में भीषण आग

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक बस में आग लग गई। बस धू-धूकर जलने लगी। लोगों ने बस मालिक को फोन कर बुलाया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर समय से पहुंचकर बुझानी शुरू की, लेकिन आग तब बुझी जब तक कि पूरी तरह से जल नहीं गई। घटना इग्नू विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर के पीछे की है। यहां खाली मैदान में 41 सीटर ट्रैवल बस खड़ी थी। उसमें अचानक आग लग गई। पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे हुई। बस संख्या UP 32 TT 1006 में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में वह धू-धू कर जलने लगी। बस के मालिक संजय कुमार यादव ने बताया- मुझे स्थानीय लोगों ने बस में आग लगने की सूचना दी। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन करते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ आग बुझानी शुरू की। बस इग्नू के पीछे मैदान में खड़ी थी। इग्नू का रीजनल सेंटर वृंदावन योजना के सेक्टर-5 स्थित है। बस मालिक तेलीबाग के गांधीनगर के रहने वाले हैं। संजय ने बताया कि बस 41 सीटों वाली थी और घटना के समय पूरी तरह खाली खड़ी थी। इसी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। हालांकि, आग लगने से बस पूरी तरह नष्ट हो गई। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

मांगलिक कार्यों में बधाई वसूलना

किन्नरों का कानूनी अधिकार नहीं

Lucknow High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नरों को दी जाने वाली बधाई पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनका कानूनी अधिकार नहीं। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किन्नरों (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों) को शुभ अवसरों पर दी जाने वाली पारंपरिक भेंट या उपहार (बधाई) लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह फैसला गोंडा जिले की किन्नर रेखा देवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करके दिया। याची ने अन्य किन्नरों द्वारा उनके "क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र" पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस प्रकार की वसूली कई वर्षों से हो रही है और इसे प्रथागत अधिकार माना जाता है। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।अदालत ने कहा, कानून के दायरे में रहते हुए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का धन, कर, शुल्क या उपकर वसूलने का कोई वैध या कानूनी आधार नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए ऐसे अधिकार ,कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। कोर्ट ने याचिका में किए गए अनुरोध को स्वीकार करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इस तरह से धन की वसूली को किसी भी तरह से वैध नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह गोंडा जिले के किन्नर समुदाय से संबंध रखता है और एक विशेष क्षेत्र में लंबे समय से बधाई वसूलने के अपने पारंपरिक अधिकार का प्रयोग करता आ रहा है। याचिका में बधाई वसूलने के लिए क्षेत्रों के सीमांकन का निर्देश देने की भी मांग की गई थी । कोर्ट ने कहा कि चूंकि बधाई वसूलने का कोई अधिकार मौजूद नहीं है, इसलिए वह इस तरह की प्रथा का संरक्षण नहीं कर सकता। इस टिप्पणी के साथ, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

सिकंदरपुर सरोसी में करोड़ों से बने खेल मैदान बदहाल

उद्घाटन के बाद रखरखाव न होने से मैदानों की हालत खराब

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जनपद के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक में मनरेगा और राज्य वित्त योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए खेल मैदानों और पार्कों की स्थिति इन दिनों गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। निर्माण के समय जिन परियोजनाओं को ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, वे आज रखरखाव के अभाव में बदहाल नजर आ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाए गए चार खेल मैदानों का उद्घाटन तो कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद उनकी नियमित देखरेख के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। परिणामस्वरूप, इन मैदानों में घास और झाड़ियां उग आई हैं, खेल उपकरण खराब हो चुके हैं और कई स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे हालात में स्थानीय खिलाड़ी और युवा इन मैदानों का उपयोग करने से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनमें निराशा का माहौल है।वहीं, राज्य वित्त योजना के तहत निर्मित एक खेल मैदान पूरी तरह तैयार होने के बावजूद बीते एक वर्ष से उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, तब भी मैदान का उपयोग न हो पाना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। उनका मानना है कि यदि समय पर इन परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जाता, तो क्षेत्र के युवाओं को खेल के लिए बेहतर अवसर मिल सकते थे।ग्रामीणों के अनुसार, इन खेल मैदानों का निर्माण तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के कार्यकाल में बड़े स्तर पर शुरू किया गया था। उस समय इन परियोजनाओं को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद कई कार्य अधूरे रह गए या फिर उनका उद्घाटन नहीं हो सका। इससे सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्लॉक के प्रभारी खंड विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित पड़े पार्क और खेल मैदानों का शीघ्र उद्घाटन कराया जाए। साथ ही, पहले से निर्मित मैदानों की स्थिति सुधारने और उनके नियमित रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं।स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही इन खेल मैदानों को पुनः उपयोग योग्य बनाया जाएगा। उनका कहना है कि केवल उद्घाटन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन परिसंपत्तियों के नियमित रखरखाव और सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि समय रहते उचित कदम उठाए गए, तो ये खेल मैदान न केवल क्षेत्र के युवाओं के लिए अभ्यास का केंद्र बन सकते हैं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल, सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

उन्नाव में सड़क किनारे मिला महिला का शव, इलाके में सनसनी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिले के सफीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक अज्ञात महिला का शव मिला। सफीपुर-मियागंज रोड पर ग्राम निहालखेड़ा के बाहर खेत के पास सड़क किनारे शव पड़ा होने की सूचना डायल 112 पर सुबह करीब 11:30 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही सफीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान फूलदुलारी (55 वर्ष) पत्नी कमलेश लोध, निवासी मोहल्ला सराय मुबारक अली, थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव के रूप में हुई। पहचान होने के बाद परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस के अनुसार, शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए हैं। इससे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है, हालांकि किसी प्रकार की हिंसा की पुष्टि नहीं हो सकी है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र में लोगों से जानकारी ली। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला वहां कैसे पहुंची और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है।

सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम

गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले उन्नाव में हाई अलर्ट

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरदोई में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर उन्नाव पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) जयप्रकाश सिंह ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजामों की जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है।एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे पर एक विशेष कंटिंजेंसी रूट तैयार किया गया है, जिस पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी नजर रखी जाएगी। जिले में विभिन्न स्थानों पर यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है।यह डायवर्जन आज शाम 6 बजे से लागू होगा और कल रात तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी भारी वाहन को मल्लावां या हरदोई की दिशा में जाने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम यातायात के दबाव को कम करने और उद्घाटन स्थल के आसपास जाम की स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है। साथ ही, आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था की गई है।एसएसपी ने स्पष्ट किया कि एंबुलेंस सहित सभी आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह छूट दी गई है और उन्हें कहीं भी रोका नहीं जाएगा। वीआईपी और वीवीआईपी आगमन को देखते हुए उनके लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाली बसों के लिए भी विशेष पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिन पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि आवागमन सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहे।सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आज शाम से ही पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और उन्हें अपनी-अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जिला प्रशासन भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। एसएसपी ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी के साथ बांगरमऊ क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां सभी इंतजाम संतोषजनक पाए गए।इसके अलावा, स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। पुलिस और प्रशासन इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

उन्नाव में कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करने का आरोप सामने आया

उन्नाव में कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करने का आरोप सामने आया है। यह आरोप हरदोई में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले लगाया गया है। कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता तन्मय श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी तन्मय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि हरदोई के मल्लावां में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका गया है। जब पुलिस अधिकारियों से इस कार्रवाई का कारण पूछा गया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला दिया। इस पर आपत्ति जताते हुए तन्मय श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के माध्यम से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार अपनी नीतियों में विफल हो चुकी है और उसे जनता तथा विपक्ष का सामना करने में डर लग रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया ।तन्मय श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें बिना किसी वैध कारण के दोबारा रोका गया, तो वह अपने आवास पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इस मुद्दे पर शाश्वत बाजपेई, सुरेंद्र कुमार और अरविंद सोनी ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासन से लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने और अनावश्यक रूप से किसी को भी नजरबंद न करने की मांग की है।

गौतमबुद्धनगर में 1 मई को विकास और जनकल्याण का महाअभियान

कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 परीक्षा 25 से 27 अप्रैल 2026 तक होगी। डीएम अतुल वत्स ने निष्पक्ष परीक्षा के निर्देश दिए। 12 केंद्रों पर 28 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने सख्त सुरक्षा, CCTV, फ्रिस्किंग और नकल रोकथाम के आदेश दिए।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में 1 मई 2026 को बड़े स्तर पर जनकल्याण और विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, बैंकिंग और आपूर्ति विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और आम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

स्वास्थ्य विभाग में बड़े कदम

कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 44 स्थानों पर टेलीमेडिसिन सुविधाओं का शिलान्यास किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों में 79 स्थानों पर डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस रूम की स्थापना का शिलान्यास भी होगा। इसके अलावा 25 मोबाइल मेडिकल वैन (मुख्यमंत्री आरोग्य रथ) को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया जाएगा। साथ ही 3 लाख सेनेटरी पैड का वितरण किया जाएगा और 201 स्थानों पर श्रमिक आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। 31 मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में ऑन-साइट मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा 25 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण, 4 एएलएस एम्बुलेंस का शुभारंभ और 10 ब्लड एनालाइजर का उद्घाटन किया जाएगा। 5 पोर्टा क्लिनिक और 15 हेल्थ वेलनेस सेंटर का शिलान्यास भी किया जाएगा, साथ ही सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। 5 नए अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा और 201 अस्पतालों में श्रमिक हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। जिला प्रशासन की तरफ से श्रमिक आवासीय कैंपों के पते और 31 अस्पतालों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है, जहां 1 मई को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी पहल

शिक्षा विभाग के तहत हल्दौनी प्राइमरी स्कूल और छजारसी कंपोजिट स्कूल का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं सेक्टर-33, YEIDA में सीएम कंपोजिट स्कूल का शिलान्यास होगा। इसके अलावा कौशल विकास के लिए 5 डिजिटल वैन और बसों का शुभारंभ किया जाएगा। श्रमिक आबादी वाले 40 स्कूलों में दूसरी पाली में कौशल विकास और अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। साथ ही 'स्कूल चलो अभियान' के तहत 25 जागरुकता कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। 24 निर्माण श्रमिक पंजीयन केंद्रों का उद्घाटन

श्रम विभाग द्वारा 24 निर्माण श्रमिक पंजीयन केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। 43 'केचो' (शिशु कक्ष) और 79 एम्बुलेंस रूम/डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा उद्योग, प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों के बीच 15 एमओयू (समझौता ज्ञापन) किए जाएंगे, जिससे श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाएं दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित हो सकें।

बैंकिंग और वित्तीय जागरुकता

बैंकों द्वारा श्रमिक बस्तियों में 26 कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले जाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव, UPI के उपयोग और स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी जागरुकता फैलाई जाएगी और नए खाते खोले जाएंगे। आपूर्ति विभाग द्वारा 1 मई 2026 को 5 किलोग्राम के 15,000 एलपीजी गैस सिलेंडरों का वितरण किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।

वाराणसी के नहिया गांव में भगवा-नीले झंडे विवाद से भड़का हिंसक बवाल

वाराणसी के नेहिया गांव में भगवा और नीले झंडे लगाने के विवाद में जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को बवाल ने हिंसक रूप ले लिया। पत्थरबाजी में ACP विदुष सक्सेना, इंस्पेक्टर, दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठी पटककर उपद्रवियों को खदेड़ा। गोसाईंपुर चौकी इंचार्ज विपिन पांडेय की तहरीर पर 11 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। शनिवार सुबह भी पीएसी के साथ 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। नहिया की दलित बस्तियों में बूटों की धमक गूंज रही है। गांव में सन्नाटा पसरा है। गिरफ्तारी के डर से नहिया गांव में दलित बस्ती के ज्यादातर युवक घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने गांव के गेट पर सीसीटीवी लगवा दिया है। जबकि 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वाराणसी मुख्यालय से 30k m दूर बाबतपुर-चौबेपुर मार्ग पर नहिया गांव में प्रवेश करने के लिए गेट बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर 'बाबा बटुक भैरव धाम' लिखा हुआ है। वहीं गांव में हाईवे से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर संत रविदास मंदिर है। जबकि हाईवे से करीब करीब 800 मीटर दूरी पर बाबा बटुक भैरव का मंदिर है। हिंदू संगठनों का दावा है कि गांव के प्रवेश गेट पर जब से निर्माण हुआ है तब से रामनवमी पर भगवा झंडा लगाया जाता रहा है। इस साल भी झंडा लगा था लेकिन 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती के जुलूस के दौरान किसी ने उसे हटाकर वहां डॉ. भीमराव अंबेडकर का झंडा लगा दिया। आरोप है कि 15 अप्रैल को इसकी सूचना मिलने के बाद शाम या रात के समय हिंदू धर्म संगठन के लोगों ने उस झंडे को तोड़कर हटा दिया। अगले दिन यानी 16 अप्रैल को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में दलित समुदाय के लोग पहुंच गए। उसके बाद लोग नारेबाजी करने लगे। दलित समुदाय के लोगों ने कहा- जब गेट पर एक विशेष झंडा लग सकता है, तो संत रविदास और बाबा साहेब का झंडा क्यों नहीं? वहीं दूसरा पक्ष इसे मंदिर का प्रवेश द्वार बताकर अपनी पुरानी परंपरा पर अड़ा रहा। इसी बात को लेकर तनाव हुआ और गुरुवार यानी 16 अप्रैल को डेढ़ घंटे हाईवे जाम रहा।

हाथरस में शिकायत की जांच के लिए डीएम का औचक निरीक्षण

जनता दर्शन में शिकायतकर्ता राधे सिसोदिया पुत्र स्व0 श्री राम खिलाड़ी निवासी गाँव बघना, पोस्ट बिसाना, तहसील व जनपद हाथरस द्वारा की गई शिकायत की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने तहसील हाथरस में संग्रह कार्यालय का किया निरीक्षण।जिलाधिकारी ने शिकायत की वास्तविकता की पुष्टि के लिए स्वयं शिकायतकर्ता के साथ तहसील पहुंचकर संग्रह कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों यथा आरसी पंजिका, रसीद बही एवं मास्टर पंजिका का गहन परीक्षण किया। इस दौरान अमीन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा फसली ऋण के सापेक्ष अमीन को दी गई धनराशि तथा बैंक में जमा कराई गई धनराशि का मिलान किया गया। जांच के प्रथम दृष्टया तथ्यों में यह सामने आया कि शिकायतकर्ता द्वारा अमीन को दी गई धनराशि की तुलना में बैंक में कम धनराशि जमा की गई है। इस गंभीर अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट धर्मेन्द्र सिंह एवं उप जिलाधिकारी सदर राज बहादुर सिंह को जांच अधिकारी नामित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि मामले की गहन जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाये जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।निरीक्षण के दौरान प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर, पटल लिपिक एवं संबंधित अमीन सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

बेटियों ने बढ़ाया मान: इंटरमीडिएट टॉपर्स को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कार एवं शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश आज दिनांक 28.04.2026 को पुलिस अधीक्षक हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपदीय टॉपर रही छात्रा कु0 दीक्षा (शिवाय इण्टर कॉलेज सादाबाद) , कु0मीरा(एस0 एन0 एस0बी0 डी0 इण्टर कॉलेज मेण्डू हाथरस) को महिला थाना हाथरस में सम्मानित किया गया । कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक हाथरस ने छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। कु0 दीक्षा द्वारा 94.20 प्रतिशत अंक व कु0 मीरा द्वारा 89.40 प्रतिशत मार्कस प्राप्त किए है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का उच्च प्रदर्शन कर रही हैं। शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति प्रदान करता है। छात्राओं को आगे भी इसी प्रकार परिश्रम करते रहने, उच्च लक्ष्य निर्धारित करने एवं निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर रहने के लिए प्रेरित कियाकार्यक्रम के दौरान छात्राओं से संवाद करते हुए पुलिस अधीक्षक हाथरस ने उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें उनके करियर के प्रति मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने छात्राओं को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार क्षेत्र का चयन करने तथा समाज एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर छात्राओं के अभिभावकों एवं गुरुजनों की भी सराहना की गई, जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से छात्राओं ने यह उपलब्धि हासिल की